



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

No. 214]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2002/श्रावण 29, 1924

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2002/SRAVANA 29, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2002

**विषय :** यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेथिलीन क्लोराइड के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 17/1/2001-डीजीएडी.—मै. गुजरात अल्केलाइज एंड कैमिकल्स लि. वदोदरा ने सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेथिलीन क्लोराइड के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने एवं पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

1. **शामिल उत्पाद:** वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद मेथिलीन क्लोराइड मेथिलीन क्लोराइड क्लोरो मिथेन विलेयक समूह का एक विलेयक है। मेथिलीन क्लोराइड एक रंगहीन, क्रियाशील द्रव है जिसमें क्लोरोफार्म जैसी गंध होती है। मेथिलीन का रसायन सूत्र  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$  सी12 हैं मेथिलीन क्लोराइड के उत्पादन के लिए दो तकनीकें/तरीके हैं तथा इन दोनों तरीकों से उत्पादित उत्पाद समान तकनीकी विशिष्टताओं वाले होते हैं। मेथिलीन क्लोराइड का प्रयोग फोटो फिल्म, बल्ब, दवाओं तथा भेषज उद्योग में किया जाता है। फोम रेजिन कारस्टिंग धूआं देने वाले पदार्थों तथा कृषि रसायनों के विनिर्माण में भी इसकी खपत होती है। इसका मुख्य उपयोग पेंट स्ट्रीपर के रूप में किया जाता है।

मेथिलीन क्लोराइड को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के सीमाशुल्क उप शीर्ष 2903.12 और आई टी सी (एच एस) कोड 29031200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है तथा वर्तमान जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

2. **घरेलू उद्योग की स्थिति:** यह याचिका मै. गुजरात अल्कलाइज एंड कैमिकल्स लि. वदोदरा, द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में निम्नलिखित कंपनियां मेथिलीन क्लोराइड का उत्पादन करती हैं—

- (क) मै. गुजरात अल्कलाइज एंड कैमिकल्स लि., वदोदरा  
(ख) मै. केमप्लास्ट सनमर, चेन्नई  
(ग) मै. एस आर एफ लिमिटेड, मुंबई

मै. केमप्लास्ट सनमर, चेन्नई ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता तथा उसका समर्थक वर्तमान याचिका दायर करने संबंधी योग्यताओं को पूरा करते हैं।

3. **शामिल देश/क्षेत्र:** वर्तमान जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

4. **समान वस्तुएं** याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु है नियमों के आशय से याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों/क्षेत्र से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. **पाटन तथा पाटन मार्जिन:**

**सामान्य मूल्य:** याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ, में सामान्य मूल्य का दावा एक अग्रणी दैनिक क्लोर अल्कली में प्रकाशित सूचना के आधार पर किया है तथा अपने सामान्य मूल्य के दावों का समर्थन संबद्ध देश/क्षेत्र में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि प्रकाशित कीमतों से संबद्ध देश/क्षेत्र में उत्पादकों को उत्पादन लागत की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर के लिए याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की परिकल्पित लागत के आधार पर किया है।

**निर्यात कीमत:** याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत का दावा कांडला पत्तन तथा डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर किया है।

सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक है जिस कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह मालूम होता है कि यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका तथा सिंगापुर के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

6. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध:** घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक सूचक जैसे उत्पादन बिक्रियां लाभ/हानि आदि से सामूहिक तथा सम्मिलित रूप से यह मालूम होता है कि घरेलू उद्योग

- को क्षति हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने घरेलू उद्यासेग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है।
7. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत:** पूर्वोक्त पैरा को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश/क्षेत्र मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण करने हेतु पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हैं।
  8. **जांच की अवधि:** वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2002 (12 माह) तक की है।
  9. **सूचना प्रस्तुत करना:** जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश/क्षेत्र के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पाटनरोधी निदेशालय, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समयान्तर के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।
  10. **समय सीमा:** वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।
  11. चूंकि पाटन रोधी जांच कार्य एक समयबद्ध प्रक्रिया है इसलिए यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या सूचना किसी भी प्रकार से अपूर्ण हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दे सकते हैं।
  12. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण:** नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उरा सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश हैं।
  13. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या अन्यथा उचित समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में पर्याप्त बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2002

**Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Methylene Chloride originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore.**

No. 17/1/2001-DGAD.—M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Vadodara, has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Methylene Chloride originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore and has requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

**1. Product Involved:** The product under investigation in the present case is Methylene Chloride. Methylene Chloride is a solvent belonging to the Chloromethane family of solvents. Methylene Chloride is a colorless, volatile liquid with a chloroform - like odour. The chemical formula of Methylene Chloride is  $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ . There are two technologies/routes for the production of Methylene Chloride and the product produced through the two routes has similar technical specifications. Methylene Chloride is used in the photo films, bulk drugs and pharmaceutical industries. It is also consumed for manufacture of foam, resin casting, fumigants and agrochemical. It is mainly used as a paint stripper.

Methylene Chloride is classified under customs sub-heading 2903.12 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act and 29031200 of the ITC (HS) Code. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

**2. Domestic Industry Standing:** The petition has been filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Vadodara. The petitioner has stated that the following companies are the producers of Methylene Chloride in India:-

- (a) M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Vadodara
- (b) M/s Chemplast Sanmar, Chennai
- (c) M/s SRF Limited, Mumbai

M/s Chemplast Sanmar, Chennai has supported the petition. The petitioner and the supporter satisfy the standing to file the present petition.

**3. Country(ies)/ Territory Involved:** The countries/territory involved in the present investigations are the European Union, South Africa and Singapore (referred to as subject countries/territory hereinafter).

**4. Like Goods:** The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject countries/territory within the meaning of the Rules.

**5. Dumping and Dumping Margin:**

**Normal Value:** The petitioner has claimed normal value in European Union on the basis of information contained in a leading journal, viz., Chlor Alkali and have supplemented their

claims of normal value on the basis of estimates of cost of production in the subject territory. The petitioner has claimed that the published prices do not permit recovery of cost of production to the producers in the subject territory. For South Africa and Singapore, the petitioner has claimed normal value on the basis of constructed cost of production.

**Export price:** The petitioner has claimed export price based on the on the data published by Kandla Port and DGCIS.

Considering the normal value and export price the dumping margins are significantly higher than the de-minimis limit.

There is sufficient evidence that the normal values of the product under consideration in the European Union, South Africa and Singapore are significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by the exporters from the European Union, South Africa and Singapore.

**6. Injury and Causal Link:** The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicates that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

**7. Initiation of Anti-Dumping Investigation:** In view of the foregoing paragraph, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

**8. Period of Investigation:** The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1<sup>st</sup> April, 2001 to 31<sup>st</sup> March, 2002 (12 months).

**9. Submission of Information:** The exporters in the subject countries/territory and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate of Anti- Dumping, Udyog Bhavan, New-Delhi -110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**10. Time Limit:** Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

2603/61/02-2

11. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.
12. **Inspection of Public File;** In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
13. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V SAPTHARISHI, Designated Authority